



परिहार की हालत स्थिर

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिहार की हालत गंभीर होने की अप्रत्याशित खबरों को मुख्यमंत्री कार्यालय ने खारिज करते हुए कहा है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।

हिन्दुस्तान

तरक्की को चाहिए नया नजरिया

शुक्रवार, 25 फरवरी 2019, नई दिल्ली, पांच पृष्ठ, 21 संस्करण

www.livehindustan.com

वर्ष 84, अंक 48, 20 पृष्ठ, मूल्य ₹ 4.50, हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ मूल्य ₹ 9.00 एवं एपटी एन के साथ मूल्य ₹ 5.50

गाजियाबाद
LIVE

सिटी

शुक्रवार 25 फरवरी 2019

हिन्दुस्तान

23

नई जीएसटी दरों से रियल स्टेट में उछाल की उम्मीद

राहत

गाजियाबाद | कार्यालय संवाददाता

जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन आवासीय संपत्तियों की बिक्री पर लगाए गए जीएसटी में कटौती कर दी है। नई दरें अप्रैल से लागू होंगी। नई दरें लागू होने के बाद से गाजियाबाद के करीब साढ़े 15 हजार लोगों को सीधे फायदा होगा। वहीं, रियल स्टेट में भी बूम आएगा।

जीडीए काउंसिल की रविवार को बैठक हुई। बैठक में रियल स्टेट को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। काउंसिल ने जीएसटी दरों में कटौती की है।

शहरों में 60 वर्ग मीटर तक के कार्पेट एरिया वाले घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। गुलशन होम्स के डायरेक्टर दीपक कपूर ने बताया कि इस फैसले का हम सभी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार यह फैसला रियल स्टेट सेक्टर और खासकर घर खरीददारों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले अंतरिम बजट में टैक्स ब्रैकेट को 5 लाख तक करना और अब जीएसटी की दरों को घटाना बहुत सराहनीय कदम है।

अजनारा इंडिया लिमिटेड के सीएमडी अशोक गुप्ता ने बताया कि काउंसिल की सिफारिशें सभी के लिए उनके सपनों के घर की दिशा में एक बड़ा कदम है। खासकर, यह आम जनता के बेहतर भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है। महागुन ग्रुप के डायरेक्टर धीरज जैन और आरजी ग्रुप के सीएमडी राजेश गोयल का कहना है कि इस फैसले के निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा। अब अफोर्डेबल हाउसिंग को और बढ़ावा मिलेगा।

साढ़े 15 हजार परिवारों को फायदा होगा

गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें करीब 15 हजार से ज्यादा फ्लैट तैयार हो रहे हैं। जीएसटी की दर कम होने से सीधे तौर पर इन लोगों को फायदा होगा। इन्हें जीएसटी की कम दर देनी पड़ेगी। जानकारों का कहना है कि जीएसटी की दर कम होने से बाजार में खरीदारों की संख्या में इजाफा होगा।

अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक फीसदी और निर्माणाधीन संपत्तियों पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने का निर्णय पूरे क्षेत्र के लिए एक सराहनीय कदम है। इससे गाजियाबाद के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। - मनोज गौड़, उपाध्यक्ष, क्रेडाई

यह चल रहे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट :

गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन, एनएच-24, एनएच-58, वेव सिटी, वसुंधरा, वैशाली, सिद्धार्थ विहार, प्रताप विहार, गोविंदपुरम, साहिबाबाद, लोनी, विजय नगर, नेहरूनगर, संजयनगर, मोहननगर, इंदिरापुरम आदि क्षेत्रों में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

नए प्रोजेक्ट आएंगे : गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में 38 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। काउंसिल के इस फैसले के बाद बिल्डरों में काफ़ी उत्साह है। ऐसे में बिल्डर और भी प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। नए प्रोजेक्ट आने से रियल स्टेट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसका फायदा सीधे तौर पर फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोगों को होगा। गाजियाबाद में एक बार फिर से रियल स्टेट में बूम आ सकता है।